पुनरीक्षण सिविल

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति आर एस नरूला के समक्ष

दविंदर नाथ-याचिकाकर्ता

बनाम

मदन गोपाल, बालक राम का पुत्र'-प्रतिवादी।

सिविल पुनरीक्षण 1976 का संख्या 1009

24 जनवरी 1977

हरियाणा शहरी (किराया और बेदखली का नियंत्रण) अधिनियम(1973 का 11) जैसा कि हरियाणा शहरी (किराया और बेदखली का नियंत्रण) संशोधन अधिनियम (1974 का 4) द्वारा संशोधित - धारा 20-ए (एल) (ए) और 24 प्रावधान - पूर्व

पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम(1949 का III) - धारा 13 - पंजाब अधिनियम के तहत किराया नियंत्रक द्वारा पारित बेदखली का एकपक्षीय आदेश - ऐसे किराया नियंत्रक के समक्ष लंबित आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन - चाहे धारा 20-ए 1 (ए) के तहत "कार्यवाही" हो -ऐसा आवेदन-क्या कार्यकारी प्राधिकारियों को हस्तांतरित किया जा सकता है।

आयोजित,हरियाणा शहरी (किराया और बेदखली का नियंत्रण) अधिनियम 1973 की धारा 20-ए को लागू करने का उद्देश्य यह था कि सिविल न्यायालयों द्वारा पारित आदेश कार्यकारी अधिकारियों की जांच के अधीन नहीं हैं। हरियाणा अधिनियम की धारा 20-ए (एल) के खंड (ए) में प्रयुक्त शब्द "कार्यवाही" का अर्थ 'अधिनियम के तहत कार्यवाही' है, जिसका अर्थ हरियाणा अधिनियम के तहत कार्यवाही होगा। पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम 1949 के तहत किराया नियंत्रक के रूप में वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए एक आवेदन हरियाणा अधिनियम में किसी भी प्रावधान द्वारा परिकल्पित नहीं है। ऐसा होने पर, ऐसा आवेदन हरियाणा अधिनियम की धारा 20-ए (एल) (ए) के अंतर्गत नहीं आएगा और उस प्रावधान के तहत कार्यकारी अधिकारियों को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर, हरियाणा अधिनियम की धारा 24 के प्रावधान में अभिव्यक्ति "इस अधिनियम के प्रारंभ होने से तुरंत पहले लंबित कार्यवाही या पारित आदेश" पंजाब अधिनियम के तहत कार्यवाही को संदर्भित करती है। (पैरा 5).

अनुच्छेद के तहत याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 में प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय इस याचिका को स्वीकार करने में प्रसन्न होगा और उस न्यायालय के संबंध में आदेश पारित करने में प्रसन्न होगा जिसके समक्ष याचिकाकर्ता यह याचिका प्रस्तुत करेगा क्योंकि आवेदन मूल रूप में वापस कर

दिए गए हैं। उचित न्यायालय में प्रस्तुति के लिए याचिकाकर्ता और दोनों अदालतों - वरिष्ठ उप न्यायाधीश, रोहतक और साथ ही विशेष कलेक्टर सह किराया नियंत्रक (उपमंडल अधिकारी (सी)) ने बेदखली के एक पक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

याचिकाकर्ता के वकील राम रंग।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता जीआर मजीठिया।

निर्णय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति आरएस नरूला, (मौखिक)

(1) मदन गोपालर (इसके बाद मकान मालिक कहा जाएगा) ने पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949 की धारा 13 के तहत याचिकाकर्ता दविंदर नाथ (जिन्हें मैं इस आदेश में किरायेदार के रूप में संदर्भित करूंगा) को बेदखल करने के लिए एक याचिका दायर की, जो 6 सितंबर, 1963 को मकान मालिक के पक्ष में एकपक्षीय फैसला सुनाया गया। सिविल कोर्ट के समक्ष बेदखली की याचिका के लंबित रहने के दौरान, हरियाणा शहरी (किराया और बेदखली का नियंत्रण) अधिनियम (हरियाणा अधिनियम संख्या 11, 1973) 27 अप्रैल, 1973 से पारित और लागू किया गया था। विद्वान वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश उन कार्यवाही को जारी रखने में सही थे जो किराया नियंत्रक के रूप में उनके समक्ष लंबित थीं। उस अधिनियम की धारा 24 के परंतुक की आवश्यकताओं के कारण मुख्य हरियाणा अधिनियम के लागू होने का समय। धारा 24 का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत किया गया है: -

> "पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949 (पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या 3, 1949) को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है:
>
> बशर्ते कि इस तरह का निरसन इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले लंबित किसी भी कार्यवाही या पारित आदेश को प्रभावित नहीं करेगा, जिसे जारी रखा जाएगा और निपटाया जाएगा या लागू किया जाएगा जैसे कि उक्त अधिनियम निरस्त नहीं किया गया था।

किरायेदार ने एक पक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए 26 अक्टूबर 1973 को एक आवेदन दिया। 2 नवंबर, 1973 को इसका नोटिस जारी करते हुए, 27 अक्टूबर, 1973 को किराया नियंत्रक के रूप में कार्य करने वाले वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा बेदखली के आदेश के निष्पादन पर रोक लगा दी गई थी। एक पक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन के लंबित रहने के दौरान, हरियाणा शहरी (किराया और बेदखली का नियंत्रण) संशोधन अधिनियम संख्या 4, 1974 पारित किया गया और 28 जनवरी, 1974 से लागू किया गया। संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा, निम्नलिखित को मूल में धारा 20-ए के रूप में शामिल किया गया था हरियाणा अधिनियम:-

"20-ए. (1) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी: -

(ए) नियंत्रकों के कार्यों को करने के लिए नियुक्त अधीनस्थ न्यायाधीशों के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियां, हरियाणा शहरी (किराया और बेदखली का नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1974 के लागू होने की तारीख से, उप-विभागीय अधिकारियों को हस्तांतरित कर दी जाएंगी। (सिविल), नियंत्रकों के कार्यों को करने के लिए धारा 2 के खंड (बी) के तहत नियुक्त किया गया;

(बी) नियंत्रक के कार्यों को करने के लिए नियुक्त अधीनस्थ न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील जिला न्यायाधीश को की जाएगी, जिसे-

अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां और ऐसे अपीलीय प्राधिकारी के आदेश का पुनरीक्षण उच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा; और

(सी) यदि नियंत्रक के कार्यों को निष्पादित करने के लिए नियुक्त अधीनस्थ न्यायाधीश के आदेश से कोई अपील अपील प्राधिकारी की शक्तियों के साथ प्रदान किए गए उपायुक्त के पास दायर की गई है, या यदि जिला न्यायाधीश के आदेश से कोई संशोधन किया गया है अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियां वित्तीय आयुक्त के पास दायर की गई हैं, उन्हें क्रमशः जिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत हस्तांतरित कार्यवाही का निपटान जिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा जैसे कि मूल रूप से उनके सामने प्रस्तुत किया गया था।

(2) एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के आवेदन को हरियाणा अधिनियम के तहत "कार्यवाही" मानते हुए विद्वान वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश ने मामले को उपमंडल अधिकारी (सिविल) को स्थानांतरित कर दिया। 27 मई, 1976 को अपने आदेश से, विशेष कलेक्टर, रोहतक, जो उप-विभागीय अधिकारी थे, ने किरायेदार के आवेदन को सुनवाई के लिए सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए इस आधार पर वापस कर दिया कि उसके पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। इससे निपटने के लिए और इसे वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा निपटाया जाना था, जिन्होंने बेदखली का आदेश पारित किया था। जब मामला वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, रोहतक के पास वापस गया, तो उन्होंने अपने आदेश, दिनांक 3 जून, 1976 (अनुलग्नक पी. 4) द्वारा माना कि हरियाणा में प्रत्येक अधीनस्थ न्यायाधीश किराया नियंत्रक के रूप में अपनी शक्तियों के संबंध में कार्यात्मक बन गया है। वह वित्तीय आयुक्त द्वारा पहले के दो निर्णयों में व्यक्त इस विचार से सहमत नहीं थे कि आवेदन को पंजाब अधिनियम के तहत किराया नियंत्रक द्वारा निपटाया जाना चाहिए। इसलिए, उन्होंने संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए किरायेदार को आवेदन वापस कर दिया। यह उपर्युक्त स्थिति में था कि किरायेदार को सही कानूनी मंच निर्धारित करने के लिए इस न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें एकपक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए उसके आवेदन को निपटाया जाना था और उस पर फैसला सुनाया जाना था।

(3) किरायेदार के विद्वान वकील श्री राम रंग ने वित्तीय आयुक्त के दो निर्णयों का उल्लेख किया है, जिस पर उप-विभागीय अधिकारी (सिविल) ने मामले को वरिष्ठ अधीनस्थ के न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वापस करने के लिए भरोसा किया था। दोनों निर्णयों को हरियाणा के वित्तीय आयुक्त श्री वीपी जौहर द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। श्रीमती पारबती और अन्य बनाम हरि चंद(1976 पीएलजे 569 (1975 रेवेन्यू लॉ रिपोर्टर 391 के अनुरूप),, लगभग ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मुख्य हरियाणा अधिनियम के लागू होने से पहले पंजाब अधिनियम के तहत किराया नियंत्रक द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया था, लेकिन एक पक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए एक आवेदन जून, 1973 में लागू होने के बाद किया गया था। प्रमुख हरियाणा अधिनियम का बल। मेरा आवेदन किराया नियंत्रक के रूप में कार्य करने वाले सिविल न्यायालय द्वारा उप-विभागीय अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया गया था, जिन्होंने आवेदन को योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया था। उस आदेश में संशोधन की याचिका वित्तीय आयुक्त द्वारा इस आधार पर स्वीकार की गई थी कि उप-विभागीय अधिकारी (सिविल) के पास किराया नियंत्रक के रूप में सिविल न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। यह न्यायालय ही था जिसने एकपक्षीय डिक्री पारित की थी जिसे इसे रद्द करने के आवेदन पर विचार करना और निर्णय लेना था। विद्वान वित्तीय आयुक्त ने माना कि किराया नियंत्रक के रूप में कार्य करने वाले अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा पारित डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन स्वीकार करने का प्रभाव सिविल कोर्ट के आदेश को संशोधित या रद्द करना होगा और चूंकि धारा 20-ए अपील का प्रावधान करती है और सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध संशोधन उन न्यायालयों के पदानुक्रम में किया जा रहा है, सिविल न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए एक आवेदन की उप-विभागीय अधिकारी द्वारा सुनवाई अंतर्निहित भावना के विपरीत होगी धारा 20-ए. उपरोक्त आधार पर उन्होंने माना कि उपमंडल अधिकारी (सिविल) पंजाब अधिनियम के तहत किराया नियंत्रक द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए सक्षम नहीं थे। छबील दास बनाम मांगे राम (1976 पीएलजे 570 (1975 रेवेन्यू लॉ रिपोर्टर 421 के अनुरूप) में वित्तीय आयुक्त का निर्णय भी इसी आशय का है। यह फिर से माना गया कि यदि उप-विभागीय अधिकारी (सिविल) सिविल न्यायालय के आदेश को रद्द कर देता है तो परिणाम यह होगा कि एक न्यायिक अधिकारी का निर्णय एक कार्यकारी अधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है।

जो स्पष्ट रूप से हरियाणा अधिनियम की धारा 20-ए की उपधारा (1) के खंड.... (बी) और (सी) की भावना के प्रतिकूल था।

(4) यदि वित्तीय आयुक्त के दो आदेश सही हैं, तो याचिका निश्चित रूप से सफल होनी चाहिए, लेकिन मकान मालिक के वकील श्री जीआर मजीठिया ने प्रस्तुत किया है कि वित्तीय आयुक्त ने मामले का निर्णय लेने में स्पष्ट रूप से गलती की थी। उन्होंने धारा की स्पष्ट भाषा के अनुसार निर्णय लेने के बजाय प्रावधान की

भावना के अनुसार निर्णय लिया। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि यदि एक पक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9, नियम 13 के तहत एक आवेदन "कार्यवाही" है, तो इसे सिविल कोर्ट द्वारा खंड (ए) के तहत कार्यकारी प्राधिकारी को स्थानांतरित किया जाना चाहिए।)

यह हरियाणा अधिनियम के लागू होने के समय लंबित था, क्योंकि उक्त प्रावधान [धारा 20-ए (1) (ए)] एक गैर-अस्थिर खंड से शुरू होता है और धारा 24 के प्रावधानों को ओवरराइड करता है। सख्ती से देखा गया तकनीकी दृष्टि से श्री मजीठिया की बात में कुछ दम है। वह इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करता है कि यदि धारा 20-ए अधिनियमित नहीं की गई थी, तो एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन जो कि संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले दायर किया गया था, उस पर भी वरिष्ठ अधीनस्थ द्वारा निर्णय लिया जाना था। न्यायाधीश और उसके विरुद्ध प्रत्येक अपील या पुनरीक्षण को जिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के पास भी जाना पड़ता था। हालाँकि, उनका जोर इस तथ्य पर है कि धारा 20-ए (एल) (ए) को धारा 24 के प्रावधान में निहित नियम के अपवाद के रूप में अधिनियमित किया गया था और इसे प्रभावी बनाया जाना चाहिए। मुख्य हरियाणा अधिनियम लागू होने के बाद वास्तव में क्या हुआ कि लंबित मामलों का फैसला सिविल कोर्ट द्वारा किया जाना था, उनके खिलाफ अपील या संशोधन कार्यकारी अधिकारियों के पास जाना था। यह महसूस किया गया कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के मद्देनजर, कार्यकारी अधिकारियों द्वारा सिविल न्यायालयों के आदेशों और निर्णयों को रद्द करने की अनुमति देना बहुत हितकर नहीं हो सकता है। इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए ही संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। संशोधन अधिनियम पारित करने के उद्देश्यों और कारणों का आधिकारिक विवरण हरियाणा शहरी (किराया और बेदखली का नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 1974 (में प्रकाशित) में निहित है।

.

हरियाणा सरकार राजपत्र असाधारण, दिनांक 2 जनवरी 1974, पृष्ठ 8 पर) निम्नलिखित शब्दों में:-

> “हरियाणा शहरी (किराया और बेदखली का नियंत्रण) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अनुसार, उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) और उपायुक्तों को किराया नियंत्रक और अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उक्त अधिनियम के लागू होने की तारीख, यानी 27 अप्रैल, 1973 से पहले लंबित कार्यवाही के निपटान में कुछ कठिनाइयों का अनुभव किया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि यह वांछनीय नहीं लगता है। .न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का कारण यह है कि लंबित मामलों के संबंध में न्यायिक अधिकारियों के निर्णय के खिलाफ अपील और संशोधन कार्यकारी अधिकारियों के समक्ष दायर किए जाने चाहिए या निर्णय लिए जाने चाहिए।
>
> विधेयक इन कठिनाइयों से निपटने और इन वस्तुओं को प्रदान करने का प्रयास करता है।

एक बार जब संशोधन अधिनियम पारित करने के उद्देश्यों और कारणों को ध्यान में रखा जाता है, जो कानूनी रूप से स्वीकार्य है, तो यह स्पष्ट है कि धारा 20-ए को लागू करने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि सिविल न्यायालयों द्वारा पारित आदेश कार्यकारी अधिकारियों की जांच के अधीन नहीं हैं। वित्तीय आयुक्त, हरियाणा

के दो निर्णय, संशोधन अधिनियम की योजना के अनुरूप हैं, जो कि विधेयक को पेश करने के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के आलोक में तय किया गया है, जो संशोधन अधिनियम बन गया।

(5) मामले के सभी पहलुओं पर समग्र रूप से विचार करने से, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि संशोधन अधिनियम की धारा 20-ए (एल) के खंड (ए) में प्रयुक्त शब्द "कार्यवाही" का अर्थ "अधिनियम के तहत कार्यवाही" है। जिसका अर्थ होगा हरियाणा अधिनियम के तहत कार्यवाही। किराया नियंत्रक के रूप में वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन की परिकल्पना हरियाणा अधिनियम के किसी भी प्रावधान में नहीं की गई है। ऐसा होने पर, ऐसा आवेदन धारा 20-ए(एल)(ए) के अंतर्गत नहीं आएगा और उस प्रावधान के तहत कार्यकारी अधिकारियों को हस्तांतरित करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरी ओर, हरियाणा अधिनियम की धारा 24 के परंतुक में "इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले लंबित कार्यवाही या पारित आदेश" की अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूप से है

पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम के तहत कार्यवाही को संदर्भित करता है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम की धारा 20-ए (एल) के खंड (ए) के साथ धारा 24 के परंतुक का मिलान करते समय और संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और वस्तुओं के प्रकाश में निर्णय लेते समय, विद्वान द्वारा लिया गया दृष्टिकोण जहां तक इसका संबंध है, वित्तीय आयुक्त, हरियाणा, मुझे इस मामले की परिस्थितियों में एकमात्र संभावित सही दृष्टिकोण प्रतीत होता है; किराया नियंत्रक के रूप में कार्य करने वाले सिविल न्यायालयों द्वारा पारित एकपक्षीय आदेशों को रद्द करने के लिए आवेदन। ऐसा होने पर, मेरा मानना है कि किराया नियंत्रक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपमंडल अधिकारी (नागरिक) (विशेष कलेक्टर, रोहतक) का 27 मई, 1976 का आदेश सही था और विद्वान वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, रोहतक का आदेश सही था। , दिनांक 3 जून 1976 (अनुलग्नक पी. 4) अवैध है और रद्द किये जाने योग्य है। विद्वान वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश ने गलती से कानून द्वारा उन्हें प्रदत्त क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर दिया है। यह उसका कर्तव्य है कि वह अपने न्यायालय द्वारा पारित बेदखली के एकपक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए किरायेदार के आवेदन पर फिर से विचार करे और उस पर निर्णय करे।

(6) मकान मालिक के विद्वान वकील श्री मजीठिया ने अंतिम रूप से तर्क दिया है कि जिन आधारों पर किरायेदार के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया गया था उनमें से एक किराए का भुगतान न करना था और इस तथ्य के बावजूद कि आदेश का निष्पादन नहीं किया गया था। बहुत समय पहले अक्टूबर 1973 में रुका था, किरायेदार द्वारा मकान मालिक को किराए के नाम पर कुछ भी भुगतान नहीं किया गया है। यह एक ऐसा मामला है जिससे इस स्तर पर मेरा कोई सरोकार नहीं है। हालाँकि, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि मकान मालिक वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, रोहतक (किराया नियंत्रक के रूप में कार्य करते हुए) को बेदखली आदेश के निष्पादन पर रोक लगाने वाले एकपक्षीय आदेश को हटाने या संशोधित करने के लिए आवेदन करता है, तो वह स्थगन आदेश की निरंतरता को सशर्त बना देगा। किरायेदार पर मकान मालिक को भुगतान करना (दोनों पक्षों की ओर से दावा किए गए अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) या उसके न्यायालय में उसे जमा करना, किराए के सभी बकाया और बाद के किराए का भुगतान महीने दर महीने जारी रखना। इस प्रकार का आदेश, जैसा कि पहले ही बताया गया है, मकान मालिक को वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय से प्राप्त करना होगा।

(7) पहले से बताए गए कारणों के लिए, मैं इस याचिका को स्वीकार करता हूं और संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, रोहतक के 3 जून, 1976 के आदेश को रद्द करता हूं और उलट देता हूं (अनुलग्नक पी. 4) और उसे बेदखली के लिए एकपक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए किरायेदार के आवेदन को वापस प्राप्त करने, मनोरंजन करने, निर्णय लेने और निर्णय लेने का निर्देश दिया (जो उनके न्यायालय द्वारा 6 सितंबर, 1973 को कानून के अनुसार पारित किया गया था। यह मामला काफी समय से लटका हुआ है। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश तीन महीने के भीतर विचाराधीन कार्यवाही का निपटान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। पक्षों को 14 फरवरी, 1977 को वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, रोहतक के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह

अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा

सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण

प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकाश जिंदल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरूग्राम, हरियाणा